[Shri Shafi Qureshi]

1967, under sub-section (3) of section 13 of the Central Silk Board Act, 1948. [*Placed in Library. See* No. LT-503/67].

(6) A copy of the Coir Industry (Amendment) Rules, 1967, published in Notification No. S.O. 1744 in Gazette of India, dated the 20th May, 1967, under Sub-section (3) of section 26 of the Coir Industry Act, 1953. [*Placed in Library. See* No. LT-504/67].

12.38 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business during the week commencing 5th June, 1967, will consist of:—

(1) Reply of the Railway Minister.

(2) General discussion on the General Budget for 1967-68.

(3) Consideration and passing of the Anti-corruption Laws (Amendment) Bill, 1967.

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : जो वक्तव्य अभी दिया गया है उस में उन्होंने एक बात को नहीं बताया है । देश में गोवध बन्द होना चाहिये इसको लेकर आन्दोलन चला था और चल रहा है । इस प्रश्न पर बड़ी उत्तेजना फैल रही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसके बारे में कोई बिल लाने जा रही है ताकि जो उत्तेजना फैली हुई है वह शान्त हो सके ?

एक और विषय की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । पिछली लोक सभा में मैंने एक सवाल उठाया था और माननीय संसद् कार्य मंत्री का इस ओर ध्यान खींचा था । देश भर में अमर बत्ती बनाने वालों के बारे में कोई कानून नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अगर बत्ती बनाने वालों के लिए कोई कानून लाने का का विचार कर रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : माननीय सदस्य को मालूम है कि जो विषय यहां आते हैं उनको बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किया जाता है और आपके दल का प्रतिनिधि भी वहां है । उन्होंने वैसा कोई विषय वहां नहीं रखा । बाद में अगली बार जब इसको वहां रखा जाएगा तो बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी इसको तय कर लेगी ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मेरे-

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : *गो रक्षा के सम्बन्ध में मैं सदन को* एक जानकारी देना चाहता हूं । सदन को मालूम है कि सरकार ने गोरक्षा महाभियान समिति से बातें करने के बाद यह निश्चय किया था कि एक कमेटी स्थापित की जाएगी जो इस प्रश्न पर विचार करके सरकार के पास अपनी सिफारिशें करेगी । सरकार ने इसके बारे में निश्चय कर लिया है और अब तक मैंने उस कमेटी की घोषणा भी कर दी होती लेकिन महाभियान समिति के लोगों ने सदस्यों के नाम देने के लिए कुछ समय मांगा है । जैसे ही उनके सदस्यों के नाम आ जाएंगे, कमेटी की घोषणा कर दी जाएगी ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : क्या यह ठीक है कि समिति के कहा है कि उस से जितने सदस्यों के नाम मांगे गए हैं, उनकी संख्या थोड़ी है और सरकारी सदस्यों की संख्या ज्यादा है ? क्या संख्या के बारे में भी कोई झगड़ा है ?

श्री जगजीवन राम : जी नहीं । उस पर कोई झगड़ा नहीं है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मैं ने अगर बत्ती उद्योग के बारे में पूछा है। उस का सत्तर नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्रम मंत्री उस के बारे में कोई बिल लाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : पश्चिमी एशिया में अरबों और इसराइल के मामले को लेकर बड़ी विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है। कार्य परामर्शदात्री समिति की उस समिति में यह तय हुआ था कि श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा के नाम पर जो प्रस्ताव है, उस पर जल्द से जल्द बहस की जायेगी। इस लिए आप की मार्फत मंत्री महोदय से मेरी यह विनती है कि अगले सप्ताह रेल मंत्री का जवाबी भाषण समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् इस प्रस्ताव को ले लिया जाये। वहां पर भी बड़ी विस्फोटक स्थिति है। अमरीका और ब्रिटेन के नाविक बेड़े वहां पर पहुंच गये हैं। रूस के लड़ाई के जहाज भी आ गये हैं। कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है। इस लिए उस प्रस्ताव को अगले सप्ताह ले लिया जाये।

Shri Narendra Singh Mahida (Anand): The Hindu Religious Endowment Bill, 1965 was introduced in the third Lok Sabha. May I know whether the Minister thinks of re-introducing that Bill?

Shri S. Kandappan (Mettur): There has been a demand from people speaking languages other than Hindi, especially the people from Madras, that the Constitution of India should be amended so as to enable English to continue indefinitely. The Government assured us that they would be amending the language Act, instead of amending the Constitution. There is no indication now that even that Act would be amended.

At the last session, we raised this question and the Government on their part kept quiet. Even before the elections the question was raised and at the time of the agitation in Madras, Government came forward with a statement that they would take steps to give statutory shape to this assurance. I would like to know when this is likely to materialise. It is serious because only last week in Kodaikanal there was a students' conference in which a resolution was passed that they were going to start some agitation if this assurance was not given statutory shape.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): I bow my head to the Business Advisory Committee because it is presided over by you. Still, permit me to air some of the misgivings that have. The Education Commission Report is before the whole country; it is being discussed by a parliamentary committee and is being written about in the newspapers. I find that the new Minister of Parliamentary Affairs who has now got used to his job has given only five hours for education demands. Education should have been our first priority this time because we are going to overhaul the whole set up of education. So, it should be given more time.

One of the burning questions in the whole of this country today is whether India should manufacture atomic bomb or not on account of the devements in China. Two hours have been given to atomic energy as if it is a tin factory which requires only two hours. I think the atomic energy department which is presided over by the Prime Minister herself and which has given rise to many controversial questions today should have received a larger measure of time than given to it now.

Mr. Speaker: All this was agreed to in the Business Advisory Committee. The report was adopted by this House.

Shri D. C. Sharma: I have got to say a lot about the Ministry of Parliamentary Affairs this time. I think

[Shri D. C. Sharma]

we have been given only one hour. I think many Members want to express their opinion about the Ministry or the Department of Parliamentary Affairs, for which I think only one hour has been given. I plead with you with folded hands, because you also come with folded hands before us when you occupy the Chair; please give more time for discussing the Demands for Grants of the Education Ministry, please give time for discussing the Education Commission report and also for the Department of Parliamentary Affairs.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I am happy to see that an official resolution has been brought by Government to have a complete and exhaustive discussion on the report of the Monopolies Inquiry Commission and the R. K. Hazari Committee report. I say that the time is good now for having a comprehensive discussion on these reports especially when the budget has been presented and is going to be discussed shortly in this House. That is one thing.

The second thing is this. We have been demanding in this House the audit report of Ruby General Insurance Company and New Asiatic Company. That was denied to us. That has been denied to us for the last seven years. Now that we will be discussing the Birla House in the R. K. Hazari Report, I request that copies of the audit report of these two companies should be laid on the Table of the House and thus be made available to us.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़): अध्यक्ष महोदय, आप को स्मरण होगा कि पिछले शुक्रवार को मैं ने आप के माध्यम से संसद्-कार्य मंत्री से यह अनुरोध किया था कि नो डे यैट नेम्ड मोशन्ज़ के संबंध में सरकार की नीति बड़ी उपेक्षापूर्ण होती आ रही है। आप से पहले लोक सभा के अध्यक्ष, श्री अयंगर, का यह नियम था कि यदि प्रति-सप्ताह नहीं, तो कम से कम दो सप्ताहों में एक नो डे यैट नेम्ड मोशन ज़रूर ले लिया जाता था और इस प्रकार से इस सदन में कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा हो जाती थी, जिन पर विचार होना आवश्यक था। पिछले शुक्रवार को आप ने कहा था कि समिति बैठ रही है और वह इस बारे में विचार करेगी कि कौन कौन सी नो डे यैट नेम्ड मोशन्ज़ स्वीकार की जायें, जिन पर यहां चर्चा हो सकती है। उस समिति की बैठक हुई और उस ने कुछ प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिये। एक प्रस्ताव यह भी स्वीकार कर लिया गया है कि पाकिस्तान को पश्चिमी राष्ट्रों की शस्त्र-सहायता दोबारा आरम्भ हो जाने के बाद भारतीय सीमाओं पर जो तनाव बढ़ता जा रहा है और इस प्रकार जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उस पर विचार किया जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी पीछे हम को अखनूर की सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं के जमाव के समाचार मिले हैं और कल परसों राजस्थान में पाकिस्तान द्वारा हमारी वायु-सीमा का अतिक्रमण किया गया है। ऐसी स्थिति में आप संसद्-कार्य मंत्री को कहें कि वह अपने आवश्यक कार्यों में इस प्रस्ताव को अवश्य सम्मिलित कर लें, ताकि इस पर चर्चा हो जाये।

मैं आप से फिर कहना चाहता हूं कि आप अनियत दिन के प्रस्तावों के संबंध में कुछ परम्परा निर्धारित करें। भले ही दो सप्ताहों में एक बार हो, लेकिन नो डे यैट नेम्ड मोशन्ज़ को अवश्य लिया जाना चाहिए। आप स्वयं संसद्-कार्य मंत्री से मिल कर इस बारे में एक निश्चित नीति निर्धारित कर दें।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, यह बजट-सेशन लम्बा चलने वाला है। हमारे यहां परिपाटी यह है कि जिस समय पार्लियामेंट बैठी हो, उस समय जो विषय देश के सामने ज्वलन्त रूप से आते हैं और जिन

का देश की जनता पर प्रभाव पड़ता है, उन पर यहां विचार हो जाया करे । इस समय देश के सामने दो संकट हैं । एक तो आर्थिक संकट है, जिस की चर्चा बजट की डीबेट में होगी । लेकिन उस से भी बड़ कर जो संकट देश के सामने है, वह सुरक्षा के संबंध में हैं । पश्चिमी एशिया में जो कुछ हो रहा है, वहां पर पीस डिस्टर्ब हो रही है, इस की मुझे चिन्ता है । लेकिन उस से भी अधिक चिन्ता मुझे इस बात की है कि जिस प्रकार वहां पर अरब देशों में इसरायल के विरुद्ध जिहाद की आवाज उठ रही है, उसी प्रकार भारत के विरुद्ध पाकिस्तान में जिहाद की आवाज उठ रही है और पश्चिमी एशिया का जिहाद और पाकिस्तान का जिहाद एक होने वाले हैं । इस लिए हम पश्चिमी एशिया की स्थिति के बारे में उदासीन नहीं रह सकते । हमारी सुरक्षा पर उस स्थिति का बहुत कुछ प्रभाव पड़ने वाला है । दुर्भाग्य से हमारी सरकार ने जल्द बाजी में कुछ बात की ह इस समय नासिर के नुमायंदे यहां आये हुए हैं । इस लिए यह आवश्यक है कि यहां पर उस के बारे में पूरी डिस्कशन हो जाय और यह निश्चित हो जाये कि भारत का दृष्टिकोण क्या है । मैं चाहता हूं कि इस विषय को प्राथमिकता दे कर इस पर इस सदन में विचार किया जाये ।

Mr. Speaker: He mentions Rajasthan; it is very urgent and important. On Monday there is a Calling Attention Notice coming up.

Shri S. S. Kothari (Mandsaur): There are a number of public corporations which are of great importance—LIC, NCDC, HSL, etc.—and periodical reports are received from them. We are not able to find time for discussion on such reports and reports like the Boothalingam Report, ARC Report on reconstitution of the Planning Commission, etc. I suggest there should be 1 hour or 2 hour discussions every week on these reports. They are of sufficient importonce, but their turn never comes. For the last 2 months, 24 motions have accumulated. They should be discussed.

श्री जार्ज फरनेंडीज (बम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, कई दिनों से सिक्किम से ऐसी खबरें आ रही हैं, खास तौर से सिक्किम महाराजा ने जब से एक अमरीकी लड़की से शादी की है, तब से....

अध्यक्ष महोदय : शादी को तो बहुत रोज हो गये, बच्चा भी हो गया ।

श्री जार्ज फरनेंडीज : तब से लेकर उन का जो हिन्दुस्तान के साथ रवैया है, उस में फर्क होता गया है और अब कई दिनों से वे हिन्दुस्तान के साथ जो संधि है, उस में फर्क करना चाहते हैं, अपने को एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाना चाहते हैं । ऐसी कई घटनायें सिक्किम और अमरीका में चल रही हैं । हम ने दो बार इस मसले पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया, लेकिन दोनों बार विषय समिति ने उन को नामन्जूर कर दिया । इस बारे में मैं इतना ही आप से कहना चाहता हूं कि जब चीनी आक्रमण वाला मामला आया, पाकिस्तान हिन्दुस्तान के रिश्ते का मामला आया, तब भी ऐसी कई घटनायें होती रहीं कि इस सदन में बहस नहीं होने दी गई, न बाहर ही बहस होने दी गई क्योंकि अखबारों पर भी सरकार का कब्जा रहता है और इस प्रकार की बहस न होने से देश को पहले से इन मामलों पर जागरूक करने का काम नहीं हो पाता । मेरा निवेदन है कि इस सिक्किम वाले मसले को जरूर अगले सप्ताह कुछ समय मिलना चाहिये और उस पर बहस होनी चाहिये ताकि जिन घटनाओं को आज हमारे देश में छिपा कर रखा जा रहा है, वे देश के सामने आ जायें ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद (नालंदा) : अध्यक्ष महोदय, मैं हजारी रिपोर्ट पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उस पर सरकारें

[श्री सिद्धेश्वर प्रसाद]

की तरफ से प्रस्ताव आ गया है, मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि इस पर जल्द से जल्द बहस हो जानी चाहिये और इस पर काफी समय दिया जाना चाहिये ।

Shri Ranga (Srikakulam): We thought this question about the Sikkim Maharaja would not be raised, because we have treaty relations with them, and it is rather a delicate matter. Now that it has been raised, I would like the Foreign Minister to take an early opportunity of clearing the clouds, so that there will not be any misunderstanding between the Sikkim Maharaja and his State on the one side and ourselves on the other.

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): Next week sometime must be provided to discuss the West Asian situation. It is a very important matter. If the budget discussion starts, we will have no opportunity to discuss it. After the Railway Minister replies, is it possible for the Parliamentary Affairs Minister to provide time for this discussion either on a private motion or on a statement from the Minister? I hope, Sir, you will agree that it is important.

Mr. Speaker: I agree it is important and that is why I have told Government that sometime must be found for it. About Sikkim, I thought it was not proper to discuss it and so I disallowed it. It has been raised now. I agree it is a delicate matter and I do not know whether it should be discussed and whether we have treaty obligations, as Mr. Ranga pointed out.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : बाद में फ्रेट-एकम्पली कर, ये लोग हमारे सामने आयेंगे । इस लिये काल एटेन्शन ले लीजिए ।

Shri S. S. Kothari: What is your opinion about having 1 hour or 2 hour discussions, Sir?

Mr. Speaker: They must find the time for it. I agree with the hon. Member, but the budget discussion and so many things are there.

Dr. Ram Subhag Singh: Sir, we shall only be too happy to accommodate the view points expressed more particularly about the No-day-yet-named motions, because three or four hon. Members including Shri Surendranath Dwivedy, Shri Prakash Vir Shastri, Shri Ranga and Shri Madhu Limaye pointed out regarding that, and also about West Asia, the danger from Pakistan, the security of this country and the Sikkim affair. But, Sir, as you know, soon after the reply of the Railway Minister the General Budget will be taken up. Of course, I will discuss the matters that have been raised here with my other colleagues. In the General Discussion on the General Budget all these things can be very aptly discussed (*Interruption*). The only difficulty is, the budget will have to be discussed in both the Houses.

Shri S. Kandappan: What about the Language Bill?

Dr. Ram Subhag Singh: I am coming to that. Unless and until the General Discussion on the General Budget is concluded here, it will be very difficult to complete the work. We are too keen that the Hazari Committee's Report should also be discussed. The Government will themselves come forward with a motion. But shortage of time is the difficulty.

Shri Prakash Vir Shastri said that no No-day-yet-named motion is given preference. That is not correct. The factual position is that three or four motions were actually covered by the motion which the hon. Minister of Food moved here. We shall see that the other motions that are there are also suitably dealt with. The Business Advisory Committee selected about five motions. We shall try to accommodate as many of those motions as possible.

There was mention about the Constitution Amendment Bill. Everything will be possible only after the Budget Debate is over because it will have to be adopted by the third week of July. There is not much time after that. I may tell Shri Mahida that the Hindu Religious Endowment Bill will also have to wait and find time. It will be taken up at a suitable time.

Then, our colleague, Shri D. C. Sharma, who has become too old now. (*Interruption*).

Shri D. C. Sharma: I do not pay court to you. Other Members come and pay court to you. Do not call me old or anything of that kind. I can pay you back in the same coin.

श्री मधु लिमये : अब तो विश्वास हो गया कि जवान हैं।

Shri D. C. Sharma: Whatever your position may be, I will not pay court to you.

Dr. Ram Subhag Singh: He pointed out about the Education Commission's Report. The same thing that I have said about others applies to that also. Atomic Energy Demands have been allotted two hours. Sir, one hour is at your discretion and if you so desire you can allot that time also.

श्री मधु लिमये : कई मंत्रियों के बारे में तरह तरह के आरोप बन रहे हैं। इस लिए जरूरी है कि आप रूबी और न्यू एशियाटिक वाली रिपोर्ट जो कि बिरला वालों के बारे में है, इस सभा पटल पर जरूर रखें।

डा० राम सुभग सिंह : इन दोनों चीजों के बारे में संबंद्ध विभागों से बात करके जो उस पर चर्चा होगी, वह करेंगे।

Shri D. C. Sharma: Sir, he must withdraw that word 'old', otherwise I will bring a no-confidence motion against him.

Dr. Ram Subhag Singh: All right. I withdraw it.

Mr. Speaker: Now, before we adjourn for lunch I may say that the Railway Budget is to be discussed now and we have got another two hours to go. All the Opposition parties have completely exhausted their time at the cost of the Congress Party. (*Interruptions*). From the papers I have got I find that DMK has 1 minute and Jan Sangh 2 minutes.

13 hrs.

Some hon. Members: No, no.

Mr. Speaker: I am speaking from the records before me. According to the note before me, only PSP has got 10 minutes and the rest of the time belongs to the Congress. I do not think any Member can make a speech in 1 minute.

श्री मधु लिमये : उस का एक इलाज है कि रेल मंत्री के जवाबी भाषण होने के बाद कुछ लोगों को सवाल पूछ लेने दिये जायें।

Mr. Speaker: I would suggest that whatever time is left today, 1½ or 2 hours, can be taken up by the hon. Members. The hon. Railway Minister will reply to the debate on Monday morning after the question hour.

Shri Rane (Buldana): Those hon. Members who could not get an opportunity to speak during the general discussion can make their points during the discussion on the demands in respect of Railway Board. This was allowed in the past.

Mr. Speaker: Yes, that can be done. Now we will adjourn for lunch.

13.02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.